भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या : 175
दिनांक 11 दिसंबर 2025

प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के अंतर्गत घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की वहनीयता

†*175. श्री बलभद्र माझीः

श्री जगदम्बिका पालः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के अंतर्गत लाभार्थियों सहित सभी उपयोगकर्ताओं के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की वहनीयता को बनाए रखने और सुनिश्चित करने के लिए नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित विशेषकर ओडिशा के ग्रामीण और जनजातीय बहुल क्षेत्रों में क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, और उत्तर प्रदेश में जिला-वार लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या पड़ोसी देशों की तुलना में हमारे देश में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमत कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा एलपीजी के स्रोत संबंधी कार्यनीति में विविधता लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं और ओडिशा जैसे पूर्वी राज्यों के लिए इस प्रयोजनार्थ किन-किन क्षेत्र-विशिष्ट उपायों पर विचार किया गया है; और

(ङ) क्या सरकार एलपीजी के लागत मूल्य की तुलना में कम वसूली होने के कारण होने वाले घाटे के लिए तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) की क्षतिपूर्ति कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के अंतर्गत घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की वहनीयता' के बारे में संसद सदस्य श्री बलभद्र माझी और श्री जगदम्बिका पाल द्वारा दिनांक 11.12.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 175 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) भारत अपनी एलपीजी ज़रूरत का लगभग 60% आयात करता है और तदनुसार, देश में एलपीजी की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में इसकी कीमतों से जुड़ी हुई हैं। जबकि औसत सऊदी सीपी (एलपीजी मूल्य निर्धारण के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक) में 21% की वृद्धि हुई (जुलाई 2023 में 385 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन से नवंबर 2025 में 466 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन तक), तो वहीं घरेलू एलपीजी की कीमतों में लगभग 22% की कमी आई (अगस्त 2023 में 1103 रुपये से नवंबर 2025 में 853 रुपये तक)।

पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी को अधिक वहनीय बनाने और उनके द्वारा एलपीजी का निरंतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, मई 2022 में सरकार ने पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर 200 रुपये (और 5 किलोग्राम कनेक्शन के लिए आनुपातिक) की लक्षित राजसहायता शुरू की। सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए अगस्त 2023 में एलपीजी की कीमतों में 200 रुपये और मार्च 2024 में 100 रुपये की कमी की गई। अक्टूबर 2023 में, सरकार ने लक्षित राजसहायता को बढ़ाकर 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर 300 रुपये (और 5 किलोग्राम कनेक्शन के लिए आनुपातिक) कर दिया।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, सरकार पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को 14.2 किलोग्राम सिलेंडर के 9 रिफिल (और 5 किलोग्राम कनेक्शन के लिए आनुपातिक) के लिए 300 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की लक्षित राजसहायता प्रदान कर रही है।

दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर का खुदरा विक्रय मूल्य वर्तमान में 853 रुपये है। पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को 300 रुपये प्रति सिलेंडर की लक्षित राजसहायता के बाद, भारत सरकार 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर 553 रुपये प्रति सिलेंडर की प्रभावी कीमत (दिल्ली में) पर उपलब्ध करा रही है। पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए, घरेलू एलपीजी की प्रभावी कीमत में लगभग 39% की कमी की गई है (अगस्त 2023 में 903 रुपये से नवंबर 2025 में 553 रुपये तक)।

पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए घरेलू एलपीजी की पहुंच और वहनीयता में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणामस्वरूप, पीएमयूवाई लाभार्थियों की प्रति कनेक्शन खपत (प्रति वर्ष लिए गए 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर रिफिल की संख्या के संदर्भ में) 3.68 (वित्त वर्ष 2021-22) से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 4.47 हो गई है। इसके अलावा, ओडिशा में पीएमयूवाई लाभार्थियों की प्रति कनेक्शन खपत (प्रति वर्ष लिए गए 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर रिफिल की संख्या के संदर्भ में) भी वित्त वर्ष 2021-22 में 3.02 से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 4.03 हो गई है। ओडिशा में पीएमयूवाई परिवारों द्वारा कुल घरेलू एलपीजी खपत वित्त वर्ष 2021-22 में 212.72 हजार मीट्रिक टन (टीएमटी) से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 317.22 टीएमटी हो गई है।

ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में एलपीजी की पहुँच और उपलब्धता में सुधार लाने के लिए, तेल विपणन कंपनियों ने दिनांक 01.04.2016 से दिनांक 31.10.2025 तक देश भर में 8,017 डिस्ट्रीब्यूटरशिप शुरू की हैं, जिनमें से 7,420 (अर्थात् 93%) ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएँ प्रदान कर रही हैं। दिनांक 01.11.2025 तक, देश भर में कुल 25,587 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप हैं, जिनमें से 966 ओडिशा राज्य में हैं। इन्हें देश भर में अवस्थित तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के 214 एलपीजी भरण संयंत्र के माध्यम से सेवाएँ प्रदान की जाती

है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, देश में एलपीजी कवरेज अप्रैल 2016 के 62% से बढ़कर अब लगभग संतृप्त हो गया है।

(ख) मध्य प्रदेश के सीधी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र (सम्पूर्ण सीधी और सिंगरौली जिलों तथा शहडोल जिले के कुछ भाग को शामिल करते हुए) में दिनांक 01.11.2025 तक पीएमयूवाई के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है:-

जिला	पीएमयूवाई कनेक्शनों की संख्या
सीधी	1.87 लाख
सिंगरौली	1.87 लाख
शहडोल	1.48 लाख

स्रोत: उद्योग आधार पर आईओसीएल

उत्तर प्रदेश राज्य में पीएमयूवाई कनेक्शनों की संख्या का जिला-वार विवरण **अनुलग्नक-क** में दिया गया है।

(ग) दिनांक 01.11.2025 तक पड़ोसी देशों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की प्रभावी कीमत निम्नानुसार है:

देश	घरेलू एलपीजी (रुपए/14.2 किलोग्राम सिलेंडर.)
भारत (दिल्ली)	553.00*
पाकिस्तान (लाहौर)	902.20
श्रीलंका (कोलम्बो)	1227.58
नेपाल (काठमांडू)	1205.72

स्रोत: पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी)

*दिल्ली में पीएमयूवाई लाभार्थियों के लिए प्रभावी लागत, जबकि गैर-पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए प्रभावी लागत 853 रुपये है।

(घ) आपूर्ति सुरक्षा सुनिश्चित करने और क्षेत्रीय व्यवधानों या भू-राजनीतिक घटनाओं से उत्पन्न जोखिमों को कम करने के लिए, कार्यनीतिक रूप से एलपीजी आयात में विविधता लाने पर काम किया जा रहा है। इस कार्यनीति के तहत, पीएसयू ओएमसी ने हाल ही में कैलेंडर वर्ष 2026 के लिए ~2.2 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) अमेरिकी मूल की एलपीजी के आयात के लिए संविदा किए हैं, जो देश की कुल एलपीजी आयात आवश्यकता का लगभग 10% है। यह पारंपरिक अरब खाड़ी क्षेत्र के बाहर एक विश्वसनीय वैकल्पिक एलपीजी आपूर्ति स्रोत स्थापित करके भारत की ऊर्जा क्षमता को मज़बूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

(ङ) वर्ष 2020-21 से वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान, सऊदी सीपी (एलपीजी मूल्य निर्धारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क) 415 डॉलर प्रति मीट्रिक टन से बढ़कर 712 डॉलर प्रति मीट्रिक टन हो गया। तथापि, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि का पूरा असर खुदरा कीमतों पर नहीं पड़ा, जिससे तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को भारी नुकसान हुआ। ओएमसी को इन नुकसानों की भरपाई के लिए, सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में ओएमसी को 22,000 करोड़ रुपये का एकमुश्त मुआवजा दिया।

वर्ष 2024-25 के दौरान एलपीजी की अंतरराष्ट्रीय कीमतें फिर से बढ़ गईं और ऊँची बनी रही हैं। तथापि, उपभोक्ताओं को अंतरराष्ट्रीय एलपीजी की कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए, बढ़ी हुई लागत

का बोझ घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं पर नहीं डाला गया, जिससे तीन ओएमसी को भारी नुकसान हुआ। इन नुकसानों के बावजूद, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने देश में वहनीय कीमतों पर घरेलू एलपीजी गैस की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की है। ओएमसी को इन नुकसानों की भरपाई के लिए, सरकार ने हाल ही में ओएमसी को 30,000 करोड़ रुपये के मुआवजे को स्वीकृति दी है।

*****

अनुलग्नक-क

"प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के अंतर्गत घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की वहनीयता" के संबंध में दिनांक 11.12.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 175 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

दिनांक 01.11.2025 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में जारी पीएमयूवाई कनेक्शनों की जिला-वार संख्या

ज़िला	कनेक्शनों की संख्या
आगरा	3,30,432
अलीगढ	3,16,016
प्रयागराज	5,84,622
अंबेडकरनगर	1,77,073
अमेठी	1,68,527
औरैया	1,35,944
आजमगढ़	2,99,777
बागपत	72,197
बहराईच	4,46,541
बलिया	2,23,093
बलरामपुर	2,24,895
बाँदा	2,47,121
बारा बांकी	3,22,753
बरेली	4,26,651
बस्ती	2,08,033
बिजनौर	3,31,388
शाहजहांपुर	3,77,535
बुलन्दशहर	3,49,931
चंदौली	1,96,789
चित्रकूट	1,31,076
देवरिया	1,98,448
एटा	1,69,144
इटावा	1,59,390
अयोध्या	2,27,209
फर्रुखाबाद	1,65,309
फ़तेहपुर	2,86,580
फिरोजाबाद	2,32,967
गौतमबुद्धनगर	78,268
गाजियाबाद	1,06,435
गाजीपुर	3,17,255
गोंडा	3,41,958
गोरखपुर	2,93,994
हमीरपुर	1,60,595
हापुड़	74,970
हरदोई	5,09,437
हाथरस	1,81,810
जालौन	1,82,702
जौनपुर	4,01,979
झांसी	2,17,502
अमरोहा	1,61,114
कन्नौज	1,72,163
कानपुर देहात	2,19,946

स्रोत: पीएसयू ओएमसी की ओर से आईओसीएल

ज़िला	कनेक्शनों की संख्या
कानपुर नगर	1,92,547
कासगंज	2,12,585
कौशांबी	1,83,284
कुशीनगर	3,15,271
खेरी	5,19,640
ललितपुर	1,94,871
लखनऊ	2,54,140
महोबा	1,19,202
महराजगंज	2,55,320
मैनपुरी	1,70,161
मथुरा	2,13,581
मऊ	1,57,593
मेरठ	1,98,833
मिर्जापुर	3,20,825
मुरादाबाद	2,80,564
मुजफ्फरनगर	2,49,834
पीलीभीत	2,33,093
प्रतापगढ़	2,72,915
रायबरेली	2,77,067
रामपुर	2,41,345
सहारनपुर	2,58,649
संभल	2,15,273
संतकबीरनगर	1,37,382
भदोही	1,96,833
शाहजहांपुर	3,57,273
शामली	1,14,132
श्रावस्ती	1,57,167
सिद्धार्थनगर	2,01,400
सीतापुर	6,00,142
सोनभद्र	2,52,398
सुल्तानपुर	2,29,370
उन्नाव	3,17,020
वाराणसी	2,51,330

स्रोत: पीएसयू ओएमसी की ओर से आईओसीएल